अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और जी20 के लिए नीतिगत प्राथमिकताएँ

एस पी शुक्ला [1] एवं आशुतोष कुमार [2]

नीति निर्माताओं ने कमजोर लोगों और अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करने, पृथ्वी ग्रह की रक्षा करने और सभी के लिए डिजिटल प्रगति का उपयोग करने का आग्रह किया। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बढ़ती अनिश्चितताओं के समय में, भारत का मजबूत प्रदर्शन एक उज्ज्वल स्थान बना हुआ है। यह एक और चुनौतीपूर्ण वर्ष के साथ महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है – जिसमें मुद्रास्फीति में गिरावट और विकास दर में गिरावट भी हो सकती है। वास्तविक रूप से हमारे नवीनतम अनुमानों से पता चलता है कि इस वर्ष वैश्विक विकास दर धीमी होकर 2.9 प्रतिशत हो सकती है, विशेषज्ञों के अनुसार 2024 में मामूली उछाल के साथ 3.1 प्रतिशत होने की उम्मीद हैं। मुख्य आंकड़ों के पीछे देखने के साथ हम उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को काफी गति प्रदान करते हुए देखते हैं। ऐसी उम्मीद है कि वे इस वर्ष वैश्विक वृद्धि में लगभग चार-पाँचवें हिस्से का योगदान देंगे, जिसमें अकेले भारत का योगदान 15 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है।

लेकिन वैश्विक विकास इंजन के रूप में अपनी भूमिका से परे, भारत सभी देशों को एक साथ लाने के लिए विशिष्ट स्थिति में है। कई चुनौतियों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों का सामना कर रहे विश्व में, यह नेतृत्व महत्तवपूर्ण है - और इसे भारत की जी20 अध्यक्षता के विषय: एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य में खूबसूरती से दर्शाया गया है। इस बारे में यह कहना है कि "एक" की यह नीति निर्माताओं और एक वैश्विक समुदाय के रूप में हम सभी के लिए क्या दर्शाती है। सबसे पहले, एक परिवार का मतलब एकजुटता और कमजोर लोगों की रक्षा करना है। वास्तविकता यह है कि विकास अभी भी निम्न स्तर पर है और कीमतों का दबाव अभी भी बहुत अधिक है। और, तीन साल के झटकों के बाद, बहुत सी अर्थव्यवस्थाएं और लोग अभी भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

दुनिया भर में, जीवन यापन की उच्च लागत के कारण कई परिवार गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं। लाखों लोग हीटिंग या खाना पकाने के लिए ईंधन नहीं खरीद सकते। एक के बाद एक आए झटकों ने गरीबी बढ़ा दी है, जिससे दशकों की प्रगति खतरे में पड़ गई है। और, खाद्य कीमतों में कुछ कमी के बावजूद, 79 देशों में रिकॉर्ड 349 मिलियन लोगों को गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। आज कमजोर लोगों का समर्थन करना सभी देशों में महत्वपूर्ण है।

राजकोषीय उपाय अस्थायी होने चाहिए और उन लोगों की रक्षा पर केंद्रित होने चाहिए जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है जो अच्छा कदम होगा, लेकिन यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश तेजी से सीमित संसाधनों और उच्च ऋण से जूझ रहे हैं। अधिकांश देशों में, बफ़र्स के पुनर्निर्माण और ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लक्षित उपायों को क्रमिक राजकोषीय मजबूती के साथ जोड़ने की आवश्यकता है।

[1] केंद्रीय विद्यालय संगठन
[2] राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो

इस बीच, मुद्रास्फीति को लक्ष्य पर वापस लाना अत्यावश्यक बना हुआ है। वहां तक पहुंचने के लिए, नीति निर्माताओं को मौद्रिक सख्ती के रास्ते पर बने रहने की जरूरत है। राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को संरेखित करने से मदद मिलेगी। वित्तीय बाज़ारों में अचानक पुनर्मूल्यांकन से बचने के लिए इन नीतिगत लक्ष्यों का स्पष्ट संचार महत्वपूर्ण है। जबकि मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक कठोरता चक्र आवश्यक है, नीति निर्माताओं को उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव के प्रति सचेत रहना चाहिए - जिसमें मजबूत अमेरिकी डॉलर और पूंजी बहिर्वाह शामिल हैं। हालाँकि जी20 की पिछली बैठक के बाद से वित्तीय स्थितियों में सुधार हुआ है, जिससे कुछ हद तक राहत मिली है, हमने देखा है कि कैसे उच्च उधार लेने की लागत भारी विदेशी ऋण बोझ वाली अर्थव्यवस्थाओं की भेद्यता को बढ़ा देती है।

कम आय वाले लगभग 15 प्रतिशत देश ऋण संकट में हैं और अतिरिक्त 45 प्रतिशत देश ऋण संकट के उच्च जोखिम में हैं। साथ ही उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, लगभग 25 प्रतिशत उच्च जोखिम में हैं और "डिफ़ॉल्ट-जैसे" उधार प्रसार का सामना कर रहे हैं।

यहां, एकजुटता का अर्थ ऋण के पुनर्गठन के लिए बेहतर तंत्र से है। जी20 के कॉमन फ्रेमवर्क के तहत, पिछले साल के अंत में अपने लेनदारों के साथ एक समझौते पर पहुंचा, और ज़ाम्बिया और घाना ऋण समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बुनियादी नियमों को स्पष्ट करने और प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

ऋण पुनर्गठन प्रयासों में तेजी लाने के लिए, आईएमएफ, विश्व बैंक और भारत की जी20 अध्यक्षता एक नया वैश्विक संप्रभु ऋण राउंड टेबल सम्मेलन बंगलुरु में आयोजित किया गया, जिसमें सभी पहली बार व्यक्तिगत रूप से मिले - और सार्वजनिक और निजी, दोनों ऋणदाताओं और देनदार देशों के लिए एक साथ काम करने, मौजूदा कमियों का आकलन करने और उनसे निपटने के सर्वोत्तम तरीकों का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में कार्य किया गया।

इस अधिक आघात-प्रवण दुनिया में, कुछ उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अतिरिक्त वित्तीय सहायता की भी आवश्यकता होगी। इसलिए, आईएमएफ के केंद्र में एक अच्छी तरह से संसाधनयुक्त वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेटवर्क पहले से कहीं अधिक महत्तवपूर्ण है।

इस बारे में सोचने की जरूरत है कि महामारी की शुरुआत के बाद से फंड ने हमारे राष्ट्रों के परिवार का समर्थन करने के लिए कैसे कदम बढ़ाया है। कुल 94 देशों के लिए $272 बिलियन से अधिक, जिसमें से लगभग $34 बिलियन तेजी से आपातकालीन वित्तपोषण वितरित किया जा रहा था, सदस्य देशों के भंडार को बढ़ाने के लिए $650 बिलियन का ऐतिहासिक एसडीआर आवंटन और एक नई फूड शॉक विंडो खाद्य सुरक्षा संकट से सबसे अधिक प्रभावित देशों के लिए संसाधनों तक त्वरित पहुंच प्रदान कर रही है। अब, हमारे परिवार के कम आय वाले और कमजोर सदस्यों के साथ एकजुट होने के लिए और

अधिक एकजुटता की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अभी भी संकट के समय में रियायती आईएमएफ वित्तपोषण का उपयोग कर सकें और भविष्य के संकटों से बच सकें। ऐसा करने की ताकत और क्षमता वाले अन्य लोगों को खड़े होने और मनोरंजन के समाधान में मदद करने की आवश्यकता है।

वैश्विक विकास

उम्मीद है कि उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का इस वर्ष और अगले वर्ष वैश्विक विकास में लगभग 80% योगदान रहेगा। (वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन)

◆ उन्नत अर्थव्यवस्थायें ◆ उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ

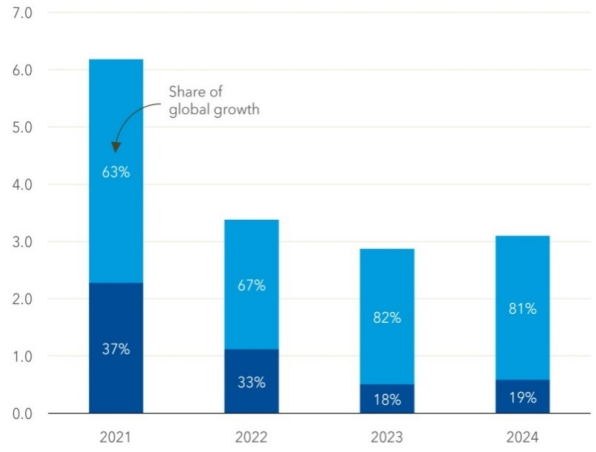

चित्र : 2, स्रोत: IMF, WEO जनवरी 2023 अपडेट, और IMF स्टाफ गणना।

गरीब देशों के लिए समर्थन बढ़ाने की आवश्यकता

कम आय वाले देशों को भारी आर्थिक चुनौतियों और वित्तपोषण आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है। वे महत्वपूर्ण नीति और वित्तीय सहायता के लिए आईएमएफ के गरीबी निवारण और विकास ट्रस्ट सहित अंतरराष्ट्रीय संस्थानों पर भरोसा करते हैं। आर्थिक रूप से मजबूत देशों की जिम्मेदारी है कि वे इस सहायता के वित्तपोषण में योगदान दें।

वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकर आईएमएफ- विश्व बैंक स्प्रिंग की वाशिंगटन बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था की नाजुक रिकवरी से लेकर वित्तीय अस्थिरता के जोखिम तक, यूक्रेन में रूस युद्ध के विखंडन से लेकर नतीजे तक। लेकिन यह जरूरी है कि वे दुनिया के सबसे गरीब देशों की बढ़ती जरूरतों को न भूलें। विशेष रूप से, इन देशों की सहायता के लिए आईएमएफ के आजमाए और परखे हुए उपकरण-गरीबी न्यूनीकरण और विकास ट्रस्ट को तत्काल पुनःपूर्ति की आवश्यकता है। महामारी के बाद से, आईएमएफ ने गरीबी न्यूनीकरण और विकास ट्रस्ट के माध्यम से 50 से अधिक कम आय वाले देशों को लगभग 24 बिलियन डॉलर के ब्याज-मुक्त ऋण का समर्थन किया है - इस प्रकार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से लेकर दुनिया के सबसे गरीब देशों और चाड और नेपाल के लिए एक विस्तृत श्रृंखला में अस्थिरता को रोकने में मदद मिली है।

अब पीआरजीटी को पर्याप्त रूप से वित्त पोषित और सब्सिडी दी जानी चाहिए ताकि ब्याज मुक्त वित्तपोषण का यह महत्वपूर्ण स्रोत जारी रह सके। यह अत्यंत प्राथमिकता का मामला है। हाल के वर्षों में कम आय वाले देशों के सामने चुनौतियाँ बहुत बढ़ गई हैं। उन्हें महामारी के साथ-साथ लगातार आर्थिक झटके भी झेलने पड़े हैं। और आज उन्हें विशेष रूप से नाजुक और संघर्ष प्रभावित राज्यों में दुर्लभ वित्तपोषण, उच्च मुद्रास्फीति, लगातार खाद्य

असुरक्षा, बढ़ती ऋण कमजोरियों और सामाजिक-राजनैतिक तनाव से अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

हमने कम आय वाले देशों के लिए अपने विकास अनुमानों को संशोधित किया है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय वृद्धि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ पकड़ने के लिए आवश्यक दरों से पीछे गिर रही है। इससे जीवन स्तर में लगातार बदलाव की दशकों पुरानी प्रवृत्ति के पलटने का खतरा है। तत्काल कार्रवाई और अधिक समर्थन के बिना, उनकी खोई हुई जमीन हासिल करने की संभावना बहुत कम है। वास्तव में, हमारा अनुमान है कि कम आय वाले देशों की अतिरिक्त वित्तपोषण ज़रूरतें - विकास में तेजी लाने और उन्हें उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ आय अभिसरण के रास्ते पर वापस लाने के लिए - 2026 तक पाँच वर्षों में लगभग $440 बिलियन की आवश्यकता होगी। विकास को बढ़ावा देने, सार्वजनिक वित्त को मजबूत करने और अधिक घरेलू राजस्व बढ़ाने के लिए घरेलू सुधारों से इस वित्तपोषण आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिलनी चाहिए। लेकिन, दाताओं और प्राप्तकर्ताओं के एक विशेष स्प्रिंग मीटिंग सत्र के दौरान रियायती वित्तपोषण पर प्रकाश डाला गया है, इसमे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की भी आवश्यकता है।

अमीर देश अपने संसाधनों को एकत्रित करके और आईएमएफ, विश्व बैंक और अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों के काम के वित्तपोषण के साथ-साथ अपने स्वयं के द्विपक्षीय विकास कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबों की सहायता कर सकते हैं। और आईएमएफ गरीब देशों में आर्थिक और वित्तीय स्थिरता बनाने के लिए अपने सभी विकास भागीदारों के साथ काम करना जारी रखेगा।

पीआरजीटी इस प्रयास का अभिन्न अंग है। यह अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए आर्थिक कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करता है जो दानदाताओं, विकास संस्थानों और निजी क्षेत्र से अतिरिक्त वित्तपोषण को उत्प्रेरित करने में मदद करता है। पीआरजीटी-समर्थित कार्यक्रम संकटग्रस्त देशों में सफल ऋण समाधान के लिए माहौल बनाने में भी केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। और जैसा कि महामारी के दौरान देखा गया पीआरजीटी झटके आने पर त्वरित आपातकालीन सहायता भी प्रदान कर सकता है।

कोविड की शुरुआत में, आईएमएफ ने पीजीआरटी के माध्यम से आपातकालीन वित्तपोषण और कार्यक्रम समर्थन को तेजी से बढ़ाया, नई प्रतिबद्धताओं के साथ अकेले 2020 में लगभग $9 बिलियन (6.5 बिलियन विशेष आहरण अधिकार) तक पहुंच गया। और कम आय वाले देशों की वित्तपोषण ज़रूरतें तेजी से बढ़ने के साथ, पीआरजीटी ऋण की मांग 2020-24 में लगभग $40 बिलियन (एसडीआर 30 बिलियन) तक पहुंचने का अनुमान है, जो ऐतिहासिक औसत से चार गुना से अधिक है।

धन की कमी

कम आय वाले देशों को महामारी से उबरने में तेजी लाने के लिए पीआरजीटी में हमारे 2021 के ऐतिहासिक सुधारों की सफलता एक फंडिंग रणनीति पर निर्भर करती है,

जिसने ऋण संसाधनों में लगभग 16.9 बिलियन डॉलर (एसडीआर 12.6 बिलियन) और 3.1 बिलियन डॉलर (एसडीआर 2.3 बिलियन) जुटाने की आवश्यकता की पहचान की है। अब तक, ऋण संसाधनों के लिए किए गए वादे की राशि लक्ष्य का लगभग तीन-चौथाई है, लेकिन सब्सिडी संसाधनों के लिए आधे से भी कम है। फंड समर्थन की रिकॉर्ड मांग और तेजी से ऊंची ब्याज दरों के कारण पीआरजीटी सब्सिडी संसाधन की जरूरतें और बढ़ गई हैं। इस प्रकार मोरक्को में इस अक्टूबर की वार्षिक बैठकों के समय धन उगाहने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रतिबद्धता की तत्काल आवश्यकता है। बैठकें दाता देशों के लिए पीआरजीटी के वित्त को ठोस आधार पर रखने के लिए एक मध्यम अवधि के समझौते पर पहुंचकर महाद्वीप के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने का एक ऐतिहासिक अवसर है।

इन संसाधनों को सुरक्षित करने में विफलता आईएमएफ की कम आय वाले देशों को बहुत आवश्यक सहायता प्रदान करने की क्षमता को खतरे में डाल देगी क्योंकि वे तेजी से बढ़ते सदमे-प्रवण दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करना चाहते हैं। संदेश स्पष्ट है कि हमारी सदस्यता को एक साथ आना चाहिए और इन कमजोर देशों के लिए समर्थन बढ़ाना चाहिए। पीआरजीटी को वित्त पोषित करना ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है

अंतरराष्ट्रीय सहयोग : जिस प्रकार अंतरराष्ट्रीय सहयोग धन एकत्रित करने की कमी को दूर कर सकता है, उसी प्रकार यह ऋण गतिरोध को तोड़ने में भी मदद कर सकता है जो कुछ देशों को रियायती वित्तपोषण तक पहुँचने से रोक रहा है। हालाँकि ऋण अनुपात अभी भी 1990 के दशक के मध्य की भारी ऋणग्रस्त गरीब देशों की (एचआईपीसी) पहल से पहले की तुलना में कम है, कम आय वाले देशों में कमजोरियाँ काफी बढ़ गई हैं और प्रवृत्ति चिंताजनक है। कम आय वाले लगभग 15 प्रतिशत देश पहले से ही ऋण संकट में हैं और अन्य 45 प्रतिशत उच्च ऋण कमजोरियों का सामना कर रहे हैं। जैसे-जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरें बढ़ती हैं, इससे और भी अधिक जोखिम पैदा होते हैं और राजकोषीय गुंजाइश सीमित हो जाती है।

इस बीच, ऋणदाता परिदृश्य में बदलाव से देशों के लिए उन ऋणों का पुनर्गठन करना अधिक कठिन हो जाता है जिनका वे भुगतान नहीं कर सकते। लेनदार पहले की तुलना में अधिक विविध हैं और समन्वय तंत्र काफी हद तक अपूर्ण हैं। भू-राजनीतिक विखंडन गरीब देशों की दुर्दशा को बढ़ा रहा है, जिससे ऋण सहित सामान्य हित के क्षेत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाना कठिन हो गया है। ऋण उपचार के लिए ग्रुप ऑफ ट्वेंटी कॉमन फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन में तेजी लाना लेनदारों और देनदारों के बीच समन्वय और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। प्रगति में तेजी लाने के लिए चाड के सफल मामले से शुरुआती सबक घाना और जाम्बिया पर लागू किया जा सकता है।

आईएमएफ, विश्व बैंक और भारत (जी20 के अध्यक्ष के रूप में) द्वारा फरवरी में शुरू किया गया वैश्विक संप्रभु ऋण राउंड टेबल सम्मेलन प्रमुख हितधारकों के बीच अधिक आम सहमति तक पहुंचने की क्षमता रखता है। आगे की प्रगति हासिल करने के लिए भी कार्य किया जा

रहा है, जब सभी राउंड टेबल प्रतिभागी-लेनदार और देनदार-स्प्रिंग मीटिंग के दौरान 12 अप्रैल 2024 को एक साथ बैठेंगे। जाहिर है, जब आईएमएफ़ 190 सदस्य देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर एक साथ मिलेंगे तो चर्चा के लिए बहुत कुछ होगा। लेकिन इन नेताओं को को दुनिया के सबसे गरीब देशों की तत्काल जरूरतों पर अन्य समस्याओं को हावी नहीं होने देना चाहिए।

चित्र : 2

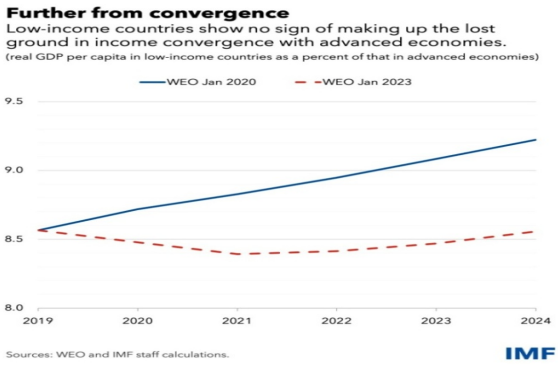

सचिन तेंदुलकर

सचिन रमेश तेंदुलकर (जन्म 24 अप्रैल 1973) एक भारतीय पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं राजापुर के सारस्वत ब्राह्मण परिवार में साउदी साकीन का नाम उनके पिता रमेश साकीत ने अपने चहेते संगीतकार सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था।जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की। उन्हें क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान बल्लेबाजों में से एक माना जाता है। वह वनडे और टेस्ट क्रिकेट दोनों में क्रमशः 18,000 से अधिक रन और 15,000 रन के साथ सर्वकालिक सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। उनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक मैन ऑफ द मैच पुरस्कार प्राप्त करने का रिकॉर्ड भी है। तेंदुलकर 2012 से 2018 तक नामांकन द्वारा राज्यसभा के संसद सदस्य थे। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर पर एक बायोपिक फिल्म 'सचिन : ए बिलियन ड्रीम्स' बनाई जा चुकी है। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है।